



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01012024-251009
CG-DL-E-01012024-251009

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 324]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 29, 2023/पौष 8, 1945

No. 324]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 29, 2023/PAUSHA 8, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2023

मामला सं. एसएसआर-11/2023

विषय: चीन जन.गण. तथा कोरिया गणराज्य से “क्लोरीनेटेड पॉलीविनायल क्लोराइड (सीपीवीसी)- चाहे यौगिक में आगे प्रसंस्कृत हो अथवा नहीं ” के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत।

फा. सं. 7/28/2023-डीजीटीआर.—1. समय समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे “अधिनियम” भी कहा गया है) और समय समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे “नियमावली” अथवा “पाटनरोधी नियमावली” भी कहा गया है), को ध्यान में रखते हुए, मै. डीसीडब्ल्यू लिमिटेड (जिसे आगे “आवेदक” कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे “प्राधिकारी” भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, जिसमें चीन जन. गण. तथा कोरिया गणराज्य (जिन्हें आगे “संबद्ध देश” भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “क्लोरीनेटेड पॉलीविनायल क्लोराइड” (जिसे आगे “संबद्ध वस्तु” अथवा “विचाराधीन उत्पाद” भी कहा गया है) के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत करने का अनुरोध किया गया है।

2. अधिनियम की धारा 9 क, (5) के अनुसार लागू पाटनरोधी शुल्क को यदि पहले नहीं हटाया जाए तो उसे लगाने की तारीख से 5 वर्षों की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाता है, और प्राधिकारी के लिए यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। इसके अनुसार, प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत रूप से साध्यांकित अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

क. पूर्ववर्ती जांच की पृष्ठभूमि

3. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित मूल पाटनरोधी जांच प्राधिकारी द्वारा 28.03.2019 को शुरू की गई थी। प्रारंभिक जांच परिणाम अधिसूचना फा. सं. 06/3/2019, दिनांक 12 जुलाई, 2019 के माध्यम से जारी किए गए थे जिनमें अनंतिम पाटनरोधी उपायों को लगाने की सिफारिश की गई थी। वित्त मंत्रालय ने दिनांक 26 अगस्त, 2019 की अधिसूचना सं. 33/2019-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा अनंतिम पाटनरोधी उपाय लगाए थे। प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 6/3/2019-डीजीटीआर दिनांक 19 फरवरी, 2020 को प्रारंभिक जांच परिणाम की पुष्टि की और 5 वर्षों की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की, जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा 7 मार्च, 2020 की अधिसूचना सं. 05/2020-सीमाशुल्क (एडीडी) के माध्यम से लगाया गया था। उक्त शुल्क यदि पहले न हटाए जाएं जो 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू थे और ये 26 अगस्त, 2024 को समाप्त होने के लिए निर्धारित हैं।

ख. विचाराधीन उत्पाद (पीपीसी)

4. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद वही है जैसा मूल जांच में परिभाषित था, जो निम्नानुसार है :

“10. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद “क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड (सीपीवीसी) है – चाहे आगे यौगिक में प्रसंस्कृत हो अथवा नहीं।”

11. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 39 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। डी जी सी आई एंड एस और डी जी सिस्टम से प्राप्त आयात आंकड़े दर्शाते हैं कि इस उत्पाद को 39042110, 39042190, 39042210, 39042290 और 39049000 के अंतर्गत आयातित किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

12. इस उत्पाद को पॉलीविनायल क्लोराइड रेजिन (सस्पेंशन पीवीसी/ मास पीवीसी) के फ्री रेडिकल क्लोरिनेशन प्रतिक्रिया के जरिए क्लोरीनेशन द्वारा उत्पादित किया जाता है और यह काफी अधिक लोचशील होता है और मानक पीवीसी के मुकाबले उच्चतर तापमान को सहन कर सकता है। क्लोरीन की मात्रा भिन्न-भिन्न विनिर्माताओं के लिए अलग-अलग हो सकती है। सामग्री को प्रसंस्करण योग्य बनाने के लिए रेजिन (सीपीवीसी यौगिक) में विभिन्न अभिवर्धक डाले जाते हैं। इन अभिवर्धकों में स्टेबलाइजर, लुब्रीकेंट्स प्रभाव परिवर्तक, प्रसंस्करण सहायक, रंग आदि शामिल हो सकते हैं।

13. सीपीवीसी आदर्श रूप से ऐसे स्व-सहायक निर्माणों के लिए उपयुक्त होता है जहां तापमान 90 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है। सीपीवीसी में अग्नि प्रतिरोधी विशेषताएं भी होती हैं, जिसमें आग लगना बहुत मुश्किल होता है और जब यह आंच के सीधे संपर्क में नहीं होता, तो स्वयं बुझ जाता है। यह आवासीय तथा वाणिज्यिक निर्माणों में जल पाइप प्रणालियों के लिए एक सामग्री के रूप में प्रयोग होता है क्योंकि यह 40 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक के तापमानों में जंगकारी जल को सहन कर सकता है। इसे आवासीय तथा वाणिज्यिक दोनों क्षेत्रों में गर्म और ठंडे जल की प्लंबिंग, अग्नि संरक्षण, जल पाइपों के पुनः प्रापण, अत्यंत ठंडे जल के पाइपों, हाइड्रोनिक पाइपिंग और वितरण (रेडिएटर, फैन क्वायल्स आदि) में गर्म और ठंडे जल के लिए प्रयोग किया जाता है तथा अनेक औद्योगिक पाइपिंग अनुप्रयोगों में प्रयोग किया जाता है।

5. चूंकि वर्तमान आवेदन एक निर्णायक समीक्षा जांच है, विचाराधीन उत्पाद वही रहेगा जो मूल अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में परिभाषित था।

ग. समान वस्तु

6. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित उत्पाद में कोई खास अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद भौतिक तथा रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। ये दानों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ता इनका एक दूसरे के स्थान पर उपयोग करते हैं। इसके अलावा, वर्तमान आवेदन पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने के लिए निर्णायक समीक्षा जांच के लिए है। समान वस्तु के मुद्दे की मूल जांच में भी प्राधिकारी द्वारा पहले से जांच की गई है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देशों से उत्पादित और आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है।

घ. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

7. यह आवेदन मै. डी सी डब्ल्यू लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक के अलावा एक अन्य उत्पादक एपीगरल लिमिटेड (जिसे पूर्व में मेघमनी फाइनकैम लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) है, ने जांच अवधि के दौरान भी उत्पादन शुरू किया है। एपीगरल लिमिटेड ने आवेदन का समर्थन किया है। यह नोट किया गया है कि आवेदक ने भारतीय व्यापारी से आयातित विचाराधीन उत्पाद की खरीद की है। आवेदक ने बताया है कि इस सामग्री को आयातित उत्पाद की कीमतों के संबंध में बाजार में वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए खरीदा गया था। यह देखा गया है कि उक्त खरीदी गई मात्रा बहुत कम है (उनके उत्पादन का लगभग 0.1%)। यह भी देखा गया है कि खरीदे गये उत्पाद का हिस्सा डीसीडब्ल्यू के उत्पादन और घरेलू बिक्रियों के संबंध में मामूली है। आवेदक ने प्रमाणित किया है कि वह संबद्ध देशों से किसी उत्पादक या भारत में किसी आयातक से संबंधित नहीं है।
8. उक्त के मद्देनजर और रिकॉर्ड में सूचना के आधार पर प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि आवेदक नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग हैं और आवेदन "घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से" दायर किया गया है। इसके अलावा, आवेदन नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता है, यद्यपि समीक्षा आवेदन में नियम 5(3) की अपेक्षाएं लागू नहीं होती हैं।

ड. संबद्ध देश

9. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन.गण. और कोरिया गणराज्य है।

च. सामान्य मूल्य

चीन जन.गण.

10. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन.गण. को एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैराग्राफ 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। आवेदक ने नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा(2) का उल्लेख किया है और यह बताया है कि चीन के उत्पादकों को यह दर्शाने का निदेश दिया जाना चाहिए कि संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने वाले उद्योग में नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-8(3) के अनुसार बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं। ऐसा नहीं होने पर चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। उक्त के मद्देनजर और चीन जन.गण. से प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा खंडन के अधीन चीन जन.गण. के लिए गैर- बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी एक पूर्व धारणा बनाई गई है और चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य का अनुमान नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार लगाया गया है। आवेदक ने चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का दावा थाइलैंड से आयात कीमत को विधिवत रूप से समायोजित करके निवल कारखाना द्वार स्तर पर पहुंचने के लिए किया है। तथापि, जांच शुरूआत

के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने चीन के लिए सामान्य मूल्य पर भारत में उत्पादन लागत के आधार पर और बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभ जोड़ने के बाद उसके अनुसार भारत में देय कीमत के आधार पर विचार किया है।

कोरिया गणराज्य

11. चूंकि कोरिया के घरेलू बाजार में प्रचलित कीमत के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है और इस उत्पाद को समर्थित कोड नहीं है, इसलिए घरेलू कीमत, आयात कीमत या निर्यात कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं हो सका था। आवेदक ने उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभ मार्जिनों के लिए युक्तिसंगत योग के साथ कोरिया गणराज्य में उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। जांच शुरूआत के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने भारत में उत्पादन लागत के आधार पर कोरिया के लिए सामान्य मूल्य पर विचार किया है।

छ. निर्यात कीमत

12. आवेदक ने बाजार आसूचना के आधार पर सीआईएफ निर्यात कीमत का दावा किया है। तथापि, आवेदक ने दलील दी है कि सीमाशुल्क आंकड़ों में दर्ज आयात कीमतें अविश्वसनीय हैं क्योंकि उपायों के कारण पक्षकारों ने बैंचमार्क के साथ सुमेलित कीमतों की सूचना सीमाशुल्क प्राधिकारियों को देने का विकल्प चुना है जो निम्नलिखित से सिद्ध होता है।
 - (क) पाटनरोधी जांच की राशि की गणना के लिए प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित बैंच मार्क के लिए आयात कीमत का सुमेलन,
 - (ख) भारतीय सीमाशुल्क को सूचित सीआईएफ निर्यात कीमत में मोटे तौर पर प्रमुख कच्ची सामग्री, पीवीसी सस्पेंशन रेजिन की कीमतों में बदलाव के साथ बदलाव नहीं हुए हैं,
 - (ग) शुल्क छूट और शुल्क प्रदत्त श्रेणी के अंतर्गत उत्पाद के ज्ञात आयातों के बीच कीमत का अंतर।
13. प्राधिकारी ने इस स्तर पर, और जांच होने तक डी जी सिस्टम के आंकड़ों के आधार पर आयात कीमत पर विचार किया है और सीआईएफ निर्यात कीमत निर्धारित की है। चूंकि सूचना सीआईएफ आधार पर है, इसलिए उसे कारखाना द्वार आधार ज्ञात करने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतरदेशीय मालभाड़ा व्यय, पत्तन व्यय और बैंक प्रभारों के लिए समायोजित किया गया है।

ज. पाटन का जारी रहना और पाटन मार्जिन

14. ऊपर यथानिर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर यह देखा गया है कि भारित औसत पाटन मार्जिन नकारात्मक है। चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, इसलिए प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों और सीमाशुल्क प्राधिकारियों से सूचना और साक्ष्य की प्राप्ति के बाद और सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा सूचित आयात कीमतों की उपयुक्त जांच के बाद पाटन की संभावना निर्धारित करेंगे।

झ. पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना

15. आवेदक ने अनुरोध किया है कि लागू पाटनरोधी उपायों से उसे घरेलू बाजार में बढ़ने में मदद मिली है और इन वर्षों में निष्पादन में सुधार हुआ है। आवेदक ने बताया है कि घरेलू उद्योग को वर्तमान अवधि में लगातार क्षति नहीं हुई है।
16. उपायों का समय बढ़ाने का अनुरोध मौजूदा पाटनरोधी जांच की समाप्ति की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना पर आधारित है। इस प्रयोजनार्थ आवेदक ने तर्क दिया है कि पाटन और क्षति की संभावना का विश्लेषण भारित औसत आयात कीमत के आधार पर उपयुक्त नहीं है क्योंकि उपाय बैंचमार्क रूप में लागू हैं, बैंचमार्क (पीवीसी सस्पेंशन रेजिन की कीमत के बजाए) से आयात कीमतें सुमेलित हैं और शुल्क मुक्त और शुल्क प्रदत्त श्रेणी के अंतर्गत सूचित आयातों की आयात कीमत में भारी अंतर है।

17. आवेदक ने संभावित पाटन मार्जिन, कीमत कटौती, क्षति मार्जिन, संबद्ध देशों में अधिशेष क्षमताओं, संबद्ध देशों में आगे और क्षमता विस्तार, संबद्ध देशों में उत्पादकों के पास मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमताओं और उनके निर्यातोन्मुख होने, तीसरे देशों में पाटन, कीमत आकर्षकता और इन निर्यातों के कारण संभावित क्षति संबंधी सूचना क्षति की संभावना को साबित करने के आधार के रूप में प्रस्तुत की है। आवेदक ने दावा किया है कि शुल्क मुक्त और शुल्क प्रदत्त आयातों में भारी अंतर के साथ आयातों की वर्तमान मात्रा स्वयं भी पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना से सिद्ध करती है। आवेदक ने शुल्क मुक्त आयातों द्वारा यथा सिद्ध शुल्क की समाप्ति की स्थिति में भारी लागत और कीमत कटौती तथा अत्यधिक पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की संभावना का दावा किया है।
18. आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना, प्रथम दृष्टया दर्शाती है कि पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में संबद्ध देशों से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना है।

ज. निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत

19. आवेदक के विधिवत रूप से सांख्यिकित आवेदन के आधार पर और पाटन तथा क्षति के जारी रहने/पुनरावृत्ति की संभावना को सिद्ध करते हुए, आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद और नियमावली के नियम 23(1ख) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में लागू शुल्क को जारी रखने की जरूरत की समीक्षा करने और इस बात की जांच करने कि क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन तथा घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करते हैं।

ट. जांच की अवधि (पीओआई)

20. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पीओआई) 1 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2023 (12 माह) की है। क्षति जांच अवधि में 2019-20, 2020-21, अप्रैल 2021- जून, 2022 और जांच की अवधि शामिल होगी।

ठ. प्रक्रिया

21. इस निर्णायक समीक्षा जांच में दिनांक 19.02.2020 की अधिसूचना सं. 6/3/2019-डीजीटीआर द्वारा प्रकाशित अंतिम जांच परिणाम, जिनमें संबद्ध देशों मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी, के सभी पहलू शामिल होंगे।
22. नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे।

ड. सूचना प्रस्तुत करना

23. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजे जाने वाले समस्त पत्र ई-मेल पत्तों jd12-dgtr@gov.in. और ad12-dgtr@gov.in जिसकी एक प्रति adg13-dgtr@gov.in तथा adv11-dgtr@gov.in, पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।
24. संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।
25. इस जांच से संगत अपने अनुरोध नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर विहित ढंग और तरीके से प्रस्तुत कर सकता है।

26. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
27. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी की अधिकारिक वेबसाइट अर्थात् <http://www.dgtr.gov.in/> को नियमित रूप से देखते रहें।

ढ. समय सीमा

28. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना प्राधिकारी को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ई-मेल पत्तों jd12-dgtr@gov.in, और ad12-dgtr@gov.in जिसकी एक प्रति adg13-dgtr@gov.in तथा adv11-dgtr@gov.in, पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। तथापि, उक्त नियमावली के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को प्राधिकारी द्वारा भेजे जाने या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
29. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है।

ण. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

30. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। ऐसा नहीं करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।
31. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
32. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
33. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/या ऐसी कोई अन्य सूचना जिसके प्रदाता द्वारा ऐसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है। ऐसी सूचना जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है या वह सूचना जिसके अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, के मामले में उस सूचना के प्रदाता के लिए प्रदत्त सूचना के साथ उसके कारणों का एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
34. सूचना के अगोपनीय अंश को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार ए डी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के आधार पर इस आशय के कारणों का एक पर्याप्त विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
35. हितबद्ध पक्षकार भी इस अधिसूचना के पैरा 32 के अनुसार दस्तावेजों के अगोपनीय अंश की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दे पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

36. पाटनरोधी शुल्क नियमावली, 1995 नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार गोपनीयता के दावे के संबंध में उसके किसी सार्थक अगोपनीय अंश या उसके पर्याप्त और पूर्ण कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
37. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है या यदि सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करना नहीं चाहता या उसके सामान्य अथवा सारांश रूप का प्रकटन करने को प्राधिकृत नहीं करना चाहता तो प्राधिकारी ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

त. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

38. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश भेज दें। अनुरोध/उत्तर/सूचना अगोपनीय अंश को परिचालित करने में विफल रहने पर किसी हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है।

थ. असहयोग

39. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है या समीक्षा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनन्त स्वरूप, संयुक्त सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2023

Case No. SSR-11/2023

Subject: Initiation of Sunset Review Investigation concerning imports of 'Chlorinated Polyvinyl Chloride (CPVC)- Whether or not further processed into compound' from China PR and Korea RP.

F. No. 7/28/2023 DGTR.—1. Having regards to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Rules" or the "Anti-Dumping Rules"), M/s DCW Limited (hereinafter referred to as the "applicant") has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority") for initiation of the sunset review investigation of antidumping duty on imports of "Chlorinated Polyvinyl Chloride" (hereinafter referred to as the "subject goods" or "product under consideration") originating in or exported from China PR and Korea RP (hereinafter referred to as "subject countries").

2. In terms of Section 9A, (5) of the Act, the anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition, and the Authority is required to review whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the same, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

A. Background of previous investigation

3. The original anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from the subject countries was initiated by the Authority on 28.03.2019. The preliminary finding was issued vide notification no. 6/3/2019 dated 12th July 2019 recommending imposition of provisional anti-dumping measures. The Ministry of Finance vide Notification No. 33/2019-Customs (ADD) dated 26th August 2019 imposed provisional anti-

dumping measures. The Authority vide Notification No. 6/3/2019 -DGTR dated February 19, 2020, confirmed the preliminary finding and recommended imposition of anti-dumping duties for a period of 5 years, which was imposed by the Ministry of Finance vide Notification No. 05/2020-Customs (ADD) on March 7, 2020. The said duties were levied for a period of 5 years, unless revoked earlier, and are set to expire on 25th August 2024.

B. Product under consideration (PUC)

4. The product under consideration in the present investigation is same as defined in the original investigation which is as follows:

“10. The product under consideration for the purpose of present investigation is “Chlorinated Polyvinyl Chloride (CPVC) - whether or not further processed into compound”.

11. The product under consideration is classified under Chapter 39 of Customs Tariff Act. Import data received from DGCI&S and DG Systems shows that the product has been imported under 39042110, 39042190, 39042210, 39042290, 39041090 and 39049000. The Customs classification is indicative only and not binding on the scope of the present investigation.

12. The product is produced by chlorination via free radical chlorination reaction of Polyvinyl Chloride resin (Suspension PVC/ Mass PVC) and is significantly more flexible and can withstand higher temperatures than standard PVC. The chlorine content may vary from manufacturer to manufacturer. Various additives are introduced into the resin (CPVC compounding) in order to make the material processable. These additives may consist of stabilizers, lubricants, impact modifiers, processing aids, pigments.

13. CPVC is ideally suited for self-supporting constructions where temperatures go up to 90°C. CPVC exhibits fire-retardant properties. It is very difficult to ignite and tends to self-extinguish when not in direct contact of flame. It is used as a material for water piping systems in residential as well as commercial construction because it can withstand corrosive water at temperatures of 40°C to 50°C or higher. It is used in hot and coldwater plumbing distribution both at residential and commercial areas, fire protection, reclaimed water piping, chilled water piping, hydronic piping and distribution (radiators, fan coils, etc.) and is used in many industrial piping applications.”

5. The present application being a sunset review investigation, the product under consideration remains the same as defined in the original final finding notification.

C. Like article

6. The applicant has claimed that there is no significant difference in the product produced by the domestic industry and the one exported from the subject countries. The product produced by the domestic industry and imported from the subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and are used by consumers interchangeably. Further, the present application is for sunset review investigation for the continued imposition of antidumping duty. The issue of like article has already been examined by the Authority in the original investigation as well. The product produced by the domestic industry is like article to the product under consideration produced and imported from the subject countries.

D. Domestic industry and standing

7. The applicant has been filed by M/s DCW Limited. Apart from the applicant, there is another producer Epigral Limited (formerly known as Meghmani Finechem Limited) which commenced production during the period of investigation itself. Epigral Limited has supported the application. It is noted that the applicant has purchased imported product under consideration from Indian trader. The applicant has stated that the material was purchased in order to ascertain factual situation in the market with regard to imported product prices. It is seen that the said purchase volume is too small (around 0.1% of their production). It is also seen that the share of the purchased product is insignificant in relation to DCW's production and the domestic sales. The applicant has certified that it is not related to any producer in the subject countries or an importer in India.
8. In view of the same, and based on information available on record, the Authority is satisfied that the applicant constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b) and the application has been made 'by or on behalf of the domestic industry'. Further, the application satisfies the requirements of standing in terms of Rule 5(3), even though the requirements of Rule 5(3) are not applicable in sunset review application,

E. Subject countries

9. The subject countries in the present investigation are China PR and Korea RP.

F. Normal value**China PR**

10. The applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and the normal value should be determined in terms of paragraph 7 of Annexure I of the Rules. The applicant has cited paragraph 8(2) of Annexure I of the Rules and have stated that the Chinese producers should be directed to show that market economy conditions prevail in the industry producing the subject goods in terms of paragraph 8(3) of Annexure I of the Rules failing which, the normal value for China PR should be determined in accordance with paragraph 7 and 8 of Annexure I of the Rules. In view of the same, the subject to rebuttal by the responding exporters from China PR, a presumption has been made regarding non-market economy for China PR and normal value of the subject goods in China PR has been estimated in terms of paragraph 7 of Annexure I of the Rules. The applicant has claimed normal value for China PR based on the import price from Thailand duly adjusted to arrive at net ex-factory level. However, for the purpose of initiation, the Authority has considered normal value for China based on price payable in India based on the cost of production in India and after addition for selling, general & administrative expenses and reasonable profits.

Korea RP

11. Since there is no information available with regard to prices prevailing in the domestic market in Korea and the product does not have dedicated code, the normal value based on the domestic price, import price or export price could not be determined. The applicant has claimed normal value based on the cost of production in Korea RP based on best estimates of the cost of the production with reasonable addition for selling, general & administrative expenses and reasonable profit margins. For the purpose of initiation, the Authority has considered normal value for Korea based on cost of production in India.

G. Export price

12. The applicant has claimed CIF export price based on market intelligence. The applicant has however contended that the import prices reported in the customs data are unreliable because due to the form of measures, the parties have resorted to reporting the prices to the customs authorities aligned to the benchmark, as established by the following.
- (a) alignment of the import price to the benchmark recommended by the Authority for computation of anti-dumping duty quantum,
 - (b) the CIF export price reported to Indian customs has, by and large, not varied with the changes in prices of principal raw material, PVC suspension resin,
 - (c) price difference between known imports of the product under duty exemption and duty paid category.
13. The Authority has considered import price based on DG Systems data at this stage, and pending investigations, and determined CIF export price. Since the information is on CIF basis, it has been adjusted for ocean freight, marine insurance, commission, inland freight expenses, port expenses and bank charges to arrive at ex-factory basis.

H. Continuation of dumping, and dumping margin.

14. Based on the normal value and the export price determined, as stated above, it is seen that the weighted average dumping margin is negative. Since the present investigation is a sunset review investigation, the Authority shall determine likelihood of dumping after receipt of information and evidence from the interested parties, and customs authorities, and appropriate examination of import prices reported to the customs authorities.

I. Likelihood of recurrence of dumping and injury.

15. The applicant has submitted that the anti-dumping measures in force have allowed it to grow in the domestic market and its performance has improved over the years. The applicant has reported that the domestic industry has not suffered continued injury in the present period.
16. The request for extension of measures is based on likelihood of recurrence of injury to the domestic industry in the event of cessation of existing anti-dumping duty. For the purpose, the applicant has contended that that an analysis of likelihood of dumping and injury is not appropriate on the basis of weighted average import price because of benchmark form of measures in force, alignment of import prices to the benchmark (instead of PVC suspension resin prices) and significant difference in import price in respect of imports reported under duty free and duty paid category.
17. The applicant has provided information on likely dumping margin, price undercutting, injury margin, surplus capacities in the subject countries, further capacity expansions in the subject countries, freely disposable capacities and export orientation of the producers in the subject countries, dumping in third country, price attractiveness and likely injury due to these exports as basis to establish the likelihood of injury. The applicant

has claimed that the current volume of imports coupled with significant difference in the price in duty free and duty paid imports itself establishes likelihood of dumping and injury to the domestic industry. The applicant has claimed likelihood of significant cost and price undercutting, and significant dumping margin and injury margin in the event of cessation of duty, as established by the duty free imports.

18. The information provided by the applicant, prima facie, shows recurrence of dumping from the subject countries and likelihood of injury to the domestic industry in case of cessation of the anti-dumping duty.

J. Initiation of sunset review investigation

19. On the basis of the duly substantiated application of the applicant, and having satisfied itself on the basis of the prima facie evidence submitted by the applicant, substantiating the likelihood of continuation/ recurrence of dumping and injury, and in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 (1B) of the Rules, the Authority hereby initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

K. Period of investigation (POI)

20. The period of investigation (POI) for the present investigation is 1st July 2022 to 30th June 2023 (12 months). The injury period for the investigation will cover the periods 2019–20, 2020–21, April 2021–June 2022 and the period of investigation.

L. Procedure

21. The sunset review investigation will cover all aspects of the final findings published vide Notification No. 6/3/2019-DGTR dated 19.02.2020, recommending the imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.
22. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, and 20 of the Rules shall be mutatis mutandis applicable in this review.

M. Submission of information

23. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at email address jd12-dgtr@gov.in and ad12-dgtr@gov.in with a copy to adg13-dgtr@gov.in and adv11-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format.
24. The known producers/ exporters in the subject countries, the governments of the subject countries through their embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
25. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time-limit set out below.
26. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
27. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority <http://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation.

N. Time limit

28. Any information relating to the present investigation should be sent to the Authority via email at the email addresses jd12-dgtr@gov.in and ad12-dgtr@gov.in with a copy to adg13-dgtr@gov.in and adv11-dgtr@gov.in within thirty days from the date of the receipt of the notice as per the Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rules, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have received within one week from the date on which it was sent by the Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
29. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

O. Submission on information on confidential basis

30. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the

Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/ submissions.

31. The parties making any submission (including Appendices/ Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.
32. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
33. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/ or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
34. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
35. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the domestic industry within 7 days of the receipt of the non-confidential version of the documents in terms of para 32 of this notification.
36. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Anti-Dumping Duty Rules, 1995 and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
37. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

P. Inspection of public file

38. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties. Failure to circulate nonconfidential version of submissions/response/information might lead to consideration of an interested party as non-cooperative.

Q. Non-cooperation

39. In case where an interested party refuses access to or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the review investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Jt. Secy. & Designated Authority